

an>

Title: Regarding misuse of funds allotted for cleaning of Loktak lake in Manipur.

श्री प्रहलाद सिंह पटेल (दमोह) : महोदया, मैं किसी का नाम नहीं लूंगा।

महोदया, मैं मणिपुर में एशिया महाद्वीप की दूसरी सबसे बड़ी झील लोकटक के बारे में सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ कि योजना आयोग जो अब नीति आयोग हो गया है, उसने पांच सौ करोड़ रुपये दिया था। लोकटक झील इतनी बड़ी है कि उसमें लेगूनस हैं। वहां पंचायतों में रहते हैं, वहां कभी आतंकवादियों का अड्डा हुआ करता था आज वह असम राइफल्स की एक यूनिट का हेडक्वार्टर है। उसके लिए पांच सौ करोड़ रुपये दिया गया और उसके लिए इस झील का एक्सेस पानी मणिपुर नदी के रूप में म्यांमार में जाता है। यह सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है और पूरी घाटी के चार-पांच जिले इस से पलते हैं। मछुआरों की संख्या वहां हजारों में है। उसकी आबादी कुल 22 लाख है, जिसमें से कम से कम चार लाख आबादी इससे अपना भरण-पोषण करती है। पांच सौ करोड़ रुपये का जो खर्च हुआ है, मैं किसी व्यक्ति का नाम नहीं लेना चाहता हूँ, लेकिन एक कम्पनी के-प्रो इफ़्ट लिमिटेड है, जिसके खिलाफ तमाम लोगों ने जांच की मांग है, मैंने भी माननीय प्रधानमंत्री जी को, नीति आयोग के उपाध्यक्ष को और सीवीसी को भी पत्र भेजा है। मैं मणिपुर का प्रभारी होने के नाते उस मुख्यालय पर गया हूँ। मैंने अपनी आंख से देखा है कि उस पैसे का भरपूर दुरुपयोग हुआ है। वह पैसा भारत सरकार का है और मणिपुर में आज जो परिस्थिति बनी हुई है 8 जुलाई से कि लगातार वहां कर्फ्यू है। हो सकता है कि लोगों को यह आरोप लगे और इस भ्रष्टाचार से ध्यान हटाने के लिए एक छात्र की गत 8 जुलाई से लाश रखी है, उसके माता-पिता उसको लेने के लिए तैयार नहीं हैं, उसके मुंह में पुलिस ने गोली मारी थी। सरकार को सिर्फ सस्पेंशन करना था। लेकिन वहां की सरकार का 8 जुलाई से आज तक रात में कर्फ्यू रहता है और दिन में हड़ताल का कर्फ्यू रहता है। आप कल्पना कीजिए कि 8 जुलाई से आज 6 अगस्त हो चुकी है, इतने लम्बे समय के बावजूद भी अगर वहां की सरकार ध्यान नहीं देती है, वहां का स्टेट बार काउंसिल, वहां की जनता मांग कर रही है कि वहां राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाए। वहां किसी प्रकार की पॉलीटिकल पार्टी की गतिविधि नहीं है। हमारी राष्ट्रीय पार्टियों को मना कर दिया गया है कि हम अपना कार्यालय न चलाएं। वहां किसी सामाजिक संगठन की गतिविधियां नहीं हो सकती हैं, मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि सदन को इसमें हस्तक्षेप करना चाहिए। मणिपुर छोटा राज्य हो सकता है, लेकिन यह सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण राज्य है, इसको बर्बाद न होने दिया जाए। वहां की राज्य सरकार को तलब किया जाना चाहिए और इन पर कार्रवाई करके भ्रष्टाचारियों को सजा दी जानी चाहिए।

माननीय अध्यक्ष : श्री पी.पी.चौधरी, श्रीमती संतोषा अहलावत, श्रीमती रीती पाठक,

श्री भैरों प्रसाद मिश्र, कुमायी शोभा कारबन्दताजे, डॉ. वरिन्द्र कुमार, श्री अजय मिश्रा टेनी और श्री सुधीर गुप्ता को श्री प्रहलाद सिंह पटेल द्वारा उठाए गए विचार के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।